डीजल के कोटे में वृद्धि करने के लिये गुजरात से प्राप्त अनुरोध

*234. **श्री राम सिंह राठवा :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने डीजल के कोटे में वृद्धि करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में डीजल की मांग कितनी थी और केन्द्रीय सरकार ने कितनी मात्रा में आपूर्ति की थी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) डीजल का राज्यवार कोटा नहीं है। फिलहाल गुजरात राज्य में डीजल की मांग को पूर्णतः पूरा किया जा रहा है।

गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात को डीजल की आपूर्ति निम्नानुसार रही है:—

वर्ष	मात्रा आपूर्तियां (मि० ट० में)
1989–90	1296390
1990–91	1328720
1991–92	1457841

तेल और गैस की खोज से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि

235. **श्री अजीत जोगी :**

श्री राधाकिशन मालवीय :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तेल और गैस की खोज संबंधी विभिन्न परियोजनाओं पर वर्षवार कितनी-कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) ऐसी कितनी परियोजनाएं विदेशी कंपनियों द्वारा शुरू की गई हैं और क्या वे सभी परियोजनाएं सफल रही हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऐसी परियोजनाओं पर कितनी राशि खर्च की गई है; और

(घ) खोज कार्य हेतु उक्त विदेशी कंपनियों को दुर्लभ विदेशी मुद्रा में भुगतान न किया जाये इसके लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और ऑयल इंडिया लि० द्वारा अन्वेषण पर खर्च की गई राशि निम्नलिखित है :—

(करोड़ रुपये)

वर्ष	राशि
1989–90	1062.89
1990–91	1168.64
1991–92	1401.35
योग :	3632.88

(ख) और (ग) गहन संवेकित अन्वेषण कार्यक्रम (आई०आई०ई०पी०) के अधीन उत्तरी-कैम्बे, कावेरी और पश्चिम बंगाल बेसिनों में पूर्व सोवियत संघ के वी/ओ मैचिनोइम्पोर्ट द्वारा तीन टर्न-की परियोजनाएं हाथ में ली गई थीं। तथापि, कोई वाणिज्यिक हाइड्रोकार्बन भण्डार स्थापित नहीं किए जा सके। वर्ष 1989-90 से 1991–92 के दौरान कुल 23117.33 लाख रुपए खर्च किए गए हैं तेल/गैस के अन्वेषण की तीसरे दौर की बोली के अधीन 5 विदेशी कम्पनियों के साथ 9

ब्लाकों के लिए उत्पादन भागीदारी करारों (पी०एस०सी०) पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल लगभग 104.28 मिलियन अमरीकी डालर खर्च किए गए हैं ।

(घ) गहन समेकित अन्वेषण कार्यक्रम परियोजनाओं का वित्त-पोषण आंशिक रूप से सोवियत क्रेडिट के जरिए किया गया था और आंशिक भुगतान "व्यापार समझौते" के तहत रुपयों में किया गया था । तीसरे दौर के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधीन व्यय का वहन विदेशी कम्पनियों द्वारा किया गया था ।

Supply of Gas to Pipavav Power Station

*236. SHRI CHIMANBHAI MEHTA :
SHRIMATI MIRA DAS :

Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to refer to answer to Unstarred Question 334 given in Rajya Sabha on the 25th November, 1992 and state :

(a) whether all the committed consumers of the HBJ pipeline are lifting gas;

(b) whether there was any commitment with regard to supply of gas to Pipavav Power Station in Gujarat;

(c) whether the need to implement the above commitments would be taken into consideration while finalising the investment plans for development of Tapti fields; and

(d) what percentage of exploited gas is allocated to Gujarat at present ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI B. SHANKARANAND) : (a) No, Sir, as gas is not available to meet the requirement of all the consumers.

(b) Subject to various factors including the development of the Mid and South Tapti fields, and in the context of some Gandhar gas being supplied to the HBJ pipeline, there was an "in principle" commitment to supply gas for a power station at Pipavav in Gujarat.

(c) The need to fulfil all commitments is taken into consideration while finalising investment plans.

(d) Approximately 22% of all gas allocations in the country have been made to various units located in Gujarat.

Additional National Highways

*237. SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV :

SHRI V. NARAYANASAMY :

Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state :

(a) the existing length of National Highways;

(b) the proposed additional length at the end of the 8th Five Year Plan period;

(c) what is the position of Maharashtra in this regard;

(d) whether the Backward Regions would be taken into consideration while constructing the New National Highways; and

(e) if so, what are the projects for the conversion of State Highways into National Highways received from Maharashtra and by when these projects are likely to be approved and implemented.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER) : (a) to (e) Existing length of National Highways in the country is 33,689 Km. Various State Governments have forwarded a number of proposals for declaration of new National Highways during the 8th Plan. This includes 11 proposals aggregating to 4679 Km. received from Govt. of Maharashtra. However, due to limited financial allocation for National Highways in the 8th Plan, it is difficult at this stage to declare new National Highways in different States including Maharashtra. The matter will be re-examined at the time of mid-term review of the 8th Plan in case allocation for National Highways is increased. Declaration of new National Highway is done keeping in view the traffic/economic requirements of the country as a whole